भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-7

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

साक्षरता दर

***7.श्रीमती रुचि वीरा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर छिहत्तर प्रतिशत है जबकि मुरादाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में औसत साक्षरता दर तिरसठ प्रतिशत है जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर मात्र सैंतालीस प्रतिशत है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा विगत दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य श्रीमती रुचि वीरा द्वारा 'साक्षरता दर' के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *7* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68 प्रतिशत थी, जबकि मुरादाबाद जिले की औसत साक्षरता दर 56.77 प्रतिशत थी, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 47.86 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा 2023-24 में किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 78.2 प्रतिशत है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 70.4 प्रतिशत है।

(ख) और (ग): भारत में शिक्षा का अधिकार, जैसा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों, जिनमें लड़कियाँ भी शामिल हैं, को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल सके। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना लड़कियों सहित सभी बच्चों के लिए समान पहुँच और समावेशी कक्षा वातावरण पर ज़ोर देती है।

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री पोषण योजना प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करती है, जिससे स्कूल में उपस्थिति और सीखने के परिणामों को बढ़ावा मिलता है। ये उपाय सामूहिक रूप से शैक्षिक रुपरेखा को सुदृढ़ करते हैं और लड़कियों सहित हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार को बनाए रखते हैं, जिससे देश भर में महिला साक्षरता सहित स्कूली शिक्षा की बेहतरी में योगदान मिला है।

इसके अलावा, देश में महिलाओं सहित वयस्कों के बीच साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए, पिछले 10 वर्षों में वयस्क शिक्षा के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) लागू की गई हैं, जैसे साक्षर भारत, पढ़ना लिखना अभियान और उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम।

साक्षर भारत: यह योजना 2009 से 2018 तक 26 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के 404 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई थी, जहां 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत और उससे कम थी। इस योजना का विशेष ध्यान महिलाओं और अन्य वंचित समूहों पर था। साक्षर भारत योजना के कार्यान्वयन के दौरान, लगभग 7.64 करोड़ शिक्षार्थियों को साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया।

पढ़ना लिखना अभियान: वित्तीय वर्ष 2020-22 के दौरान, देश में वयस्क शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना "पढ़ना लिखना अभियान" लागू की गई, जिसके तहत लगभग 48.16 लाख लोगों को साक्षर बनाया गया।

समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ (उल्लास) - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम: भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, वर्ष 2022-2027 तक, केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), अर्थात् "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)" को कार्यान्वित कर रही है ताकि देश भर में निरक्षरों में साक्षरता को बढ़ावा देने में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान किया जा सके। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, महिलाओं और अन्य कमजोर समुदायों आदि पर केंद्रित है।

यह योजना हाइब्रिड मोड में कार्यान्वित की जा रही है, जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता सहित मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन मोड अपनाने की सुविधा मिलती है। उल्लास, कर्तव्यबोध (कर्तव्य की भावना) से प्रेरित होकर, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए स्कूल प्लेटफॉर्म और स्वयंसेवा के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव का उपयोग करते हुए, भारत को 'जन-जन साक्षर' बनाने के दृष्टिकोण के साथ काम करता है।

आज की तिथि तक, देश भर में 1.2 करोड़ महिलाओं सहित 1.7 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी साक्षरता परीक्षा - मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (एफएलएनएटी) में शामिल हो चुके हैं। उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत चार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नामतः लद्दाख, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा पूरी तरह से साक्षर हो गए हैं।

****